Industrial Estates?

The Minister of Industry in the Ministry of Commerce and Industry (Shri Kanungo): (a) 77.

(b) 220 sheds.

(c) The layout plans etc. have not yet been finalized.

Licences for Industries in Delhi

1646. Shri Shiv Charan Gupta: Will the Minister of **Commerce and Industry** be pleased to state:

(a) the number and names of factories/industries for which licences were issued by Government during the last 5 years in Delhi; and

(b) which of these factories/industries have been established in Delhi?

The Minister of Industry in the Ministry of Commerce and Industry (Shri Kanungo): (a) Information regarding the names of factories/industries for which licences are issued under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 in Delhi and all other States are published periodicially in the "Journal of Industry and Trade", copies of which are available in the Library of the House.

(b) A statement on the basis of available information is laid on the Table of the House. [*See* **Appendix II, annexure No. 90**].

उत्तर प्रदेश में खेतिहर मजदूरों को रोजगार

१६४७ { **श्री सरजू पांडेय :**
श्री ज० ब० सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल के बाद खेतिहर मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार के सहयोग से कोई योजना कार्यान्वित करने जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है ?

योजना, श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). खेती की मन्दी के दिनों में निर्माण-कार्य में ग्रामीण जन-शक्ति का उपयोग करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के कहने पर दो पाइलट प्रोजेक्ट चालू किये। दूसरी शृंखला के अन्तर्गत २० और पाइलट प्रोजेक्ट १९६१-६२ तथा १९६२-६३ के खेती के मंदी के दिनों में चालू करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार को अलाट किये गये हैं। पहली तथा दूसरी शृंखला के अन्तर्गत चालू होने वाले तमाम पाइलेट प्रोजेक्टों का पूरा खर्चा १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष के अन्त तक भारत सरकार ने दिया। १९६२-६३ के वित्तीय वर्ष से केन्द्र इन प्रोजेक्टों का खर्चा ५० प्रतिशत अनुदान तथा ५० प्रतिशत ऋण के रूप में देगा। पहले चरण में (अर्थात् जो अवधि प्रोजेक्ट चालू होने से एक वित्तीय वर्ष के खेती की मन्दी के दिनों में शुरू होती है तथा दूसरे वित्तीय वर्ष के अन्त में समाप्त होती है) प्रत्येक प्रोजेक्ट की लागत २ लाख रुपये है।

उत्तर प्रदेश में इन पाइलेट प्रोजेक्टों के अन्तर्गत लघु सिंचाई, रिंग बांध निर्माण, ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाना, नालियों को फिर से बनाना, सड़कों का निर्माण इत्यादि काम आते हैं और इन पर १९६२-६३ के वित्तीय वर्ष के अन्त तक ४४ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। १९६१-६२ तथा १९६२-६३ के खेती की मन्दी के दिनों में इन प्रोजेक्टों में लगभग २४,००० खेतिहर मजदूरों को १०० दिन के लिए रोजगार मिलने की सम्भावना है।